महत्वपूर्ण एवं खास

अपहृत ग्रामीणों को नक्सलियों ने रिहा किया

सुकमा (आरएनएस)। जिले के कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बटेर से मुखबिरी के शक में अपहरण किए गए पांच ग्रामीणों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। इनमें एक युवती भी शामिल थी, सभी ग्रामीण अपने गांव पहुंचे गये हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनमें से दो ग्रामीणों के साथ नक्सलियों ने मारपीट किया है। नक्सलियों को शक था कि डेढ़ माह पूर्व हुई मुठभेड़ में इन ग्रामीणों ने मुखबिरी की थी। अपहरण के बाद सर्व आदिवासी समाज ने भी नक्सलियों से ग्रामीणों को छोड़ देने की अपील की थी। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अपहृत ग्रामीणों का पुलिस से कोई संबंध नहीं है। नक्सलियों ने अगवा किए गए सभी ग्रामीणों को छोड़ दिया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि नक्सलियों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस आदि में ग्रामीण शामिल नहीं हो रहे थे, इसी के चलते ग्रामीणों को अगवा किया गया था।

जांजगीर-चांपा से 3 लाख की नशीली दवा खपाने की थी तैयारी, पांच आरोपी गिरफ्तार

कोरबा(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नशीली दवा का कारोबार एक बार पुनः पैर पसारने लगा है। दूसरे जिले से आकर बाइक में घूम घूम कर दवाइयां बेची जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपित को गिरफ्तार कर उनके पास 256 कफ सिरफ, 1408 कैप्सूल व दो दोपहिया वाहन जप्त किया गया है। जांजगीर-चांपा से नशीली कफ सिरफ व टेबलेट काफी मात्रा में लेकर एक व्यक्ति के कोरबा आने की सूचना पुलिस को मिली। कोतवाली पुलिस ने टीम बना कर आरोपितों की पतासाजी में जुटी थी। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गोमाता चौक पर कुछ संदिग्ध लोग खड़े है और उनके पास नशीली दवाइयां है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने इमलीडुग्गु चौक के पास एक मोटर सायकल क्रमांक सीजी 12 एटी 1290 में दो लोगों को गोमाता चौक की ओर से आते देखा। रोक कर वाहन की जांच करते हुए पूछताछ की गई। तब बाइक चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम सिकंदर खान उर्फबाबा निवासी मस्जिद मोहल्ला सोनारीन घाट चांपा व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शफीक मेमन उर्फ फजलू निवासी गोमाता चौक कोरबा बताया। उसके हाथ मे एक पीले रंग की बोरी मिली। जांच करने पर बोरी में 148 शीशी कफसिरफ और 448 नशीला टेबलेट बरामद की गई। दूसरी टीम द्वारा बरबसपुर के पास कोरबा आ रही स्कूटी क्रमांक जेएच सात एफ7725 को रोककर जांच की। स्कूटी मनीष जागृति चला रहा था, धीरेन्द्र शुक्ला निवासी गोकुलनगर हाउसिंग बोर्ड बीच में बैठ कर पीले रंग की बोरी रखा था, वहीं स्कूटी के पीछे बैठा चंद्रेश महंत उर्फ मनीष निवासी उरगा बस्ती थाना उरगा अपने पास एक कार्टून रखा था। सामानों की जांच किए जानने पर बोरी में 115 नशीला कफ सिरफ तथा कार्टून में 960 नशीला टेबलेट मिला। सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 22 सी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि सिकंदर खान अपने साथ नशीली दवाइयों को लेकर आया था। पुलिस ने बताया कि सिकंदर ने कोरबा में अन्य आरोपितों को दवाइयां डिलीवरी करने के लिए बुलाया था। मनीष जागृतिए धीरेंद्र शुक्ला व चंद्रेश महंत आरोपित सिकंदर के पास से नशीली दवा लेकर जा रहे थे, तब उरगा पुलिस ने पकड़ा। शेष बचे हुई नशीली दवा को शफीक मेमन उर्फ फजलु खरीदा था। जिसे छिपाने के लिए आरोपित पुराने बस स्टैंड की ओर जा रहे थे, तभी कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया।

रायगढ़ जिले ने रचा इतिहास, कोविड टीकाकरण शत-प्रतिशत पूर्ण

» कोविड टीकाकरण में देश के टॉप जिलों में शुमार हुआ रायगढ़ का नाम

» 16 जनवरी से शुरू हुआ सफर 298 दिनों में ही पहुंचा मुकाम पर

» 10 लाख 68 हजार 456 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य हुआ पूरा

» दोनों डोज मिलाकर लगे 21 लाख से अधिक टीके

रायगढ़। कोरोना महामारी से बचाव के लिए हो रहे वैक्सीनेशन कार्य में रायगढ़ जिले ने इतिहास रच दिया है। कोविड टीकाकरण के मामले में रायगढ़ जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। रायगढ़ में कोविड टीकाकरण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इससे रायगढ़ देश के उन चुनिंदा टॉप जिलों में शामिल हो गया है जहां कोविड टीकाकरण का कार्य सबसे पहले पूरा किया गया है।

रायगढ़ में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई टीकाकरण की यह मुहिम आज 9 नवम्बर को अपने मुकाम पर पहुंच गई है। पिछले 298 दिनों में कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व व जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरे जिला प्रशासन की टीम ने अथक मेहनत व परिश्रम से टीकाकरण के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा किया है। रायगढ़ जिले को 10 लाख 68 हजार 456 लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य मिला था, जिसे पूरा करते हुए इतने लोगों को टीके के दोनों डोज लगाई जा चुकी है। जिले में अब तक पहला व दूसरा डोज मिलाकर जिले में कुल 21 लाख 47 हजार 169 टीके लगाए गए है।

रायगढ़ जिला टीकाकरण के मामले में पूरे प्रदेश में शुरू से अव्वल रहा है और आज की उपलब्धि ने जिले को टीकाकरण के मामले में न केवल राज्य में शीर्ष में स्थापित किया है बल्कि रायगढ़ का नाम देश के उन चुनिंदा टॉप जिलों में शामिल हो गया है जिन्होंने सबसे पहले अपनी आबादी को टीके की दोनों डोज लगाई है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास बन जाती है, आज यदि राज्य स्तर पर देखे तो जहां पहले पायदान पर रायगढ़ है वहीं दूसरे पायदान पर चल रहा महासमुंद में 65 प्रतिशत ही टीकाकरण हो पाया है अर्थात पहले और दूसरे पायदान के बीच 35 प्रतिशत का फर्क है जो कि रायगढ़ जिले में कलेक्टर भीम सिंह के कुशल नेतृत्व व सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल के मार्गदर्शन में बनायी गई रणनीति, स्वास्थ्य विभाग की दिनरात की अथक मेहनत व प्रशासन के सभी विभागों की टीम भावना के साथ किए गए कार्य के सफलता की कहानी कह रहा है।

साझेदारी से पूरी हुयी जिम्मेदारी-कलेक्टर भीम सिंह- जिले की इस उपलब्धि पर कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि कोविड टीकाकरण सबसे पहले पूरा करना एक अहम उपलब्धि है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य सभी विभागों के अधिकारियों से लेकर जमीनी अमले, जनप्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों की आपसी साझेदारी का परिणाम है जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी करने में हमे सफलता मिली। एक टीम की तरह सभी ने काम किया। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि टीकाकरण के लिए सुनियोजित प्लानिंग, उसका क्रियान्वयन, टीके की उपलब्धता, उसका मोबिलाइजेशन, ग्राउंड लेवल पर लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करना, हिचक रहे लोगों की शंका दूर कर टीका लगवाने की चुनौती इन तमाम पहलुओं पर सभी ने सामूहिक जिम्मेदारी से काम किया जिससे जिले ने वर्तमान वैश्विक महामारी से सुरक्षा और बचाव के परिपेक्ष्य में यह अहम उपलब्धि हासिल की है।

अग्रेसिव स्ट्रेटेजी ने दिलाई सफलता - रायगढ़ जिले को पूर्ण रूप से टीकाकृत बनाने के लिए कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में शुरूआत से ही अग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनायी गई। एक ओर जहां अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर संचालित किए गए वहीं दूसरी ओर लोगों तक हर संभव माध्यम से संवाद स्थापित कर टीके का महत्व तथा जल्द टीकाकरण कराने के फायदों को बताया गया। कुछ लोगों के बीच टीकाकरण को लेकर जो भ्रांतियां व्याप्त थी, उसे भी दूर किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, सरपंचों का भी सहयोग लिया गया। जिसका परिणाम हुआ कि जिले में टीकाकरण को लेकर स्वस्फूर्त सकारात्मक माहौल निर्मित हुआ। शुरू में जहां वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों को टीके लगाए गए, वहीं अंतिम चरणों में रणनीति बदलते हुए लोगों के घरों पर दस्तक दी गई। जिससे टीकाकरण की रफ्तार बनी रही। कलेक्टर सिंह ने प्रशासनिक स्तर पर लगातार उच्चाधिकारियों से संपर्क कर टीके की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की। सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल के मार्गदर्शन में सभी विभागों ने एक टीम की तरह कार्य किया। जिसका नतीजा यह निकला कि आज रायगढ़ छत्तीसगढ़ में टीकाकरण पूरा करने वाला न केवल सबसे पहला जिला बना बल्कि पूरे देश में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाले टॉप जिलों में शामिल हो गया।

26 जून को 1 दिन में सबसे अधिक 1 लाख 43 हजार को लगे थे टीके- रायगढ़ के लिए 26 जून का दिन ऐतिहासिक रहा। कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में महा टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दिन पूरे प्रदेश में अब तक एक दिन में सबसे अधिक 1 लाख 43 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। टीकाकरण केन्द्रों में लोगों की लम्बी कतारें देखने को मिली, लोगों के उत्साह ने इस अभियान को टीका महोत्सव बना दिया।

अजगरबहार को तहसील बनाने दो दिसंबर तक ली जाएंगी आपत्तियां और सुझाव

» मुख्यमंत्री बघेल ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर की थी अजगरबहार को तहसील बनाने की घोषणा

कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पिछले स्वतंत्रता दिवस पर अजगरबहार को नई तहसील का दर्जा देने की घोषणा जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है। राज्य सरकार ने कोरबा जिले के अजगरबहार को नई तहसील का दर्जा देने के लिए पहले ही छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है और दो दिसंबर तक इस संबंध में नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव मंगाए गए हैं। समय सीमा में मिले सुझावों और आपत्तियों का निराकरण कर अजगरबहार को नई तहसील का दर्जा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल के कोरबा प्रवास के दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने प्रशासनिक सुगमता और आमजनों की सहुलियत के लिए अजगरबहार को तहसील बनाने की मांग की थी। उस समय भी मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई थी और उन्होंने अजगरबहार को तहसील बनाने की घोषणा की थी। अजगरबहार के नई तहसील बन जाने से इस क्षेत्र के दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले लोगों को अपने जमीन-जायदाद संबंधी कामों में सहुलियत होगी।

अजगरबहार को तहसील बनाने के लिए राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पिछले महीने की चार तारीख को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना प्रकाशन के दिन से साठ दिन के भीतर नागरिकों से इस संबंध में लिखित सुझाव एवं आपत्तियां भी मांगी गई है। इस हिसाब से अजगरबहार को नई तहसील बनाने के संबंध में आपत्तियां और सुझाव दो दिसंबर तक लिए जाएंगे।

नई तहसील में 41 गांव, नौ पटवारी हल्के और लगभग 22 हजार होगी जनसंख्या - अजगरबहार अभी कोरबा तहसील का हिस्सा है। अजगरबहार की कोरबा तहसील मुख्यालय से दूरी 25 से 28 किलोमीटर है। वहीं इसके आगे के दूरस्थ गांव कोरबा तहसील मुख्यालय से 55 से 60 किलोमीटर तक भी स्थित हैं। अजगरबहार के तहसील बन जाने से इस इलाके के 41 गांवो के लोगों को अपने राजस्व संबंधी प्रकरणों के लिए कोरबा नहीं आना पड़ेगा। नई अजगरबहार तहसील में 13 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। मकबूजा और गैरमकबूजा रकबा मिलाकर यह तहसील 14 हजार 476 हेक्टेयर क्षेत्रफल की होगी। इस तहसील में शामिल 41 गांवो की कुल जनसंख्या लगभग 22 हजार है। तहसील क्षेत्र में तीन हजार 508 खातेधार होंगे। तहसील में एक राजस्व निरीक्षक मण्डल अजगरबहार और दस पटवारी हल्के होंगे। तहसील की उत्तरी सीमा सूरजपुर जिले की उदयपुर तहसील से मिलेगी। दक्षिणी और पूर्वी सीमा कोरबा तहसील से और पश्चिमी सीमा पोड़ी-उपरोड़ा तहसील से लगी होगी।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से गर्भवती फुलवा हुई कुपोषण मुक्त

» आंगनबाड़ी में दिए गए पौष्टिक आहार से शरीर में खून की कमी भी हुई दूर

कोरबा। बच्चों एवं महिलाओं को कुपोषण और एनीमिया से बचाने के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से लबेद की रहने वाली श्रीमती फुलवा कुपोषण और एनीमिया से मुक्त हो गई है। गर्भावस्था के शुरूआती दिनों में फुलवा का हिमोग्लोबिन स्तर काफी कम हो गया था। आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले अण्डा, मूंगफली लड्डू एवं अन्य पौष्टिक आहार से गर्भवती फुलवा का हिमोग्लोबिन स्तर प्रसव के समय बढ़कर 10 ग्राम हो गया। आंगनबाड़ी केन्द्र में दिए गए नियमित पौष्टिक आहार से फुलवा ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। जन्म के दौरान बालक का वजन साढ़े तीन किलोग्राम था। गर्भावस्था के दौरान आंगनबाड़ी में फुलवा को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत दूध, लड्डू, पापड़, आचार एवं पौष्टिक चिक्की भी दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा फुलवा को नियमित रूप से पौष्टिक

आहार संबंधी सलाह भी दिया गया। जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण एवं एनीमिया को जड़ से समाप्त करने कार्ययोजना बनाकर काम किया जा रहा है। अभियान के तहत कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। सभी हितग्राहियों को गर्म भोजन के साथ रेडी-टु-ईट दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से गृह भेंट करके हितग्राहियों को व्यक्तिगत साफ-सफाई, स्वास्थ्य जांच एवं पौष्टिक आहार के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान फुलवा का गर्भवती पंजीयन मदनपुर सेक्टर के आंगनबाड़ी केन्द्र लबेद में कराया गया। पंजीयन कराने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नियमित आंगनबाड़ी केन्द्र आने के लिए कहा। स्वास्थ्य जांच के दौरान शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए अच्छे और पौष्टिक आहार लेने के लिए कहा गया। आंगनबाड़ी केन्द्र में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत फुलवा को नियमित पौष्टिक आहार भी दिया गया। पंजीयन के समय फुलवा का वजन लगभग 37 किलोग्राम था एवं हिमोग्लोबिन स्तर भी बहुत कम था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा फुलवा के घर गृह भेंट किया गया। फुलवा को महतारी जतन के बारे में बताया गया और प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्र में भोजन करने के लिए बुलाया गया। फुलवा को समय-समय पर खाने-पीने और साफ-सफाई के बारे में भी बताया गया। फुलवा को उसके घर में मुनगा व पपीता को लगाने की सलाह दी गई व भोजन में मुनगा भाजी खाने के लिए विशेष रूप से सलाह दिया गया। फुलवा को आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली रेडी टू ई फुड का सेवन करने का सलाह दिया गया। साथ ही आयरन गोली खाने की विधि के बारे में भी बताया गया। फुलवा ने सलाह को मानकर प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्र भोजन करने आती थी। जिस दिन नहीं आ पाती थी उस दिन उन्हें टिफिन में पौष्टिक आहार दिया जाता था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानीन द्वारा उन्हें समय पर जरूरी टीका लगवाने का भी सलाह दिया गया। जिसे मानकर फुलवा ने सभी टीका लगवाई व सभी प्रकार की जरूरी स्वास्थ्य जांच भी करवाई। फुलवा का प्रसव कुदमुरा अस्पताल में हुआ। बच्चे का वजन साढ़े तीन किलो था। फुलवा ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। प्रसव के समय फुलवा का वजन 49 कि.ग्रा. व एच.बी. 10.08 ग्रा. था। गृह भेठ के दौरान फुलवा को बताया गया कि बच्चें को 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराने के लिए कहा गया। फुलवा ने अपने बच्चे को 6 माह तक केवल स्तनपान कराया व सभी टीका भी लगवाई। फुलवा ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत दिए गए पौष्टिक आहार एवं सलाह के द्वारा एक स्वस्थ्य बालक को जन्म दिया साथ ही स्वयं पोषण स्तर के सामान्य श्रेणी में रही।

थाना बागो क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परला में चालित थाना का आयोजन

कोरबा। 8 नवम्बर 2021 को बांगो थाना अंतर्गत ग्राम परला में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक अभिषेक वर्मा एवम पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ईश्वर त्रिवेदी के मार्गदर्शन में चलित थाना का आयोजन किया गया ।

उक्त अवसर पर ग्राम के सचिव, पंचगन, ग्रामीण पुरुष एवम महिलाए अत्यधिक संख्या मे उपस्थित आए । ग्रामीणों से ग्राम की समस्या के संबंध मे पूछताछ करने पर ग्रामीणों द्वारा थाना क्षेत्र मे स्थित बैंकों से आवश्यक जानकारी और सहयोग नही मिलना बताए। बैंकों द्वारा पासबुक में पैसा आने और निकासी का एंट्री नही करने से और मोबाइल नम्बर को खाता से लिंक नही करने से बैंक खाते में पैसा के संबंध मे जानकारी नही होने से बहुत परेशानी का सामना करना बताए। जिस पर ग्रामीणों को अगले दिवस ही बैंक जाकर बैंक प्रबंधक से मिलकर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही परला ग्राम हाथी विचरण क्षेत्र होने से अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की समझाइश दिया गया। ग्रामीणों को शराब पीकर वाहन न चलाने ए वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करने ए वाहन का बीमा कराकर रखने ए वाहनों मे नंबर प्लेट में नंबर अंकित कराने की समझाइश दिया गया । परला ग्राम कोरिया और अंबिकापुर जिला के समीपस्थ होने से बर्तन और जेवर चमकाने के बहाने ठगी करने वालो से अत्यधिक सतर्क और सावधान रहने की समझाइश दिया गया। ग्रामीणों को महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के संबंध मे एवम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के संबंध मे थाना प्रभारी राजेश पटेल द्वारा अवगत कराया गया।

ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्वे की तिथि एक माह बढ़ी, अब 30 नवंबर तक चलेगा सर्वेक्षण

» सीजीक्यूडीसी मोबाइल ऐप में हो रहा सर्वेक्षण, सबसे अधिक नगर निगम कोरबा क्षेत्र से मिले आवेदन

कोरबा। ओबीसी और ईब्ल्यूएस सर्वे की तिथि बढ़ा दी गई है। सर्वेक्षण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। सर्वेक्षण की अंतिम तिथि पहले 30 अक्टूबर 2021 निर्धारित थी जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है। कोरबा जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण-संगणना के दौरान अब तक दो लाख 90 हजार 023 आवेदन मिल चुके हैं। इस सर्वेक्षण में दोनों वर्गों के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक लाख 15 हजार 545 लोगों ने और ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख 74 हजार 478 लोगों ने आवेदन किया है। सबसे अधिक आवेदन नगर निगम क्षेत्र कोरबा में मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक आवेदन पाली विकासखण्ड से हैं। जिले में मोबाइल एप्प के माध्यम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण-गणना का काम तेजी से जारी है। यह सर्वेक्षण 30 नवंबर तक जारी रहेगा। जिले में ईडब्ल्यूएस वर्ग के सर्वेक्षण में अभी तक 24 हजार 318 आवेदन और ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण मे दो लाख 65 हजार 705 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 96 हजार 556 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 18 हजार 989 आवेदन मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी के लिए एक लाख 69 हजार 149 और ईडब्ल्यूएस के लिए पांच हजार 329 आवेदन अभी तक मिले हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए छत्तीसगढ़ क्रांटीफायबल डाटा आयोग बनाया है। अभी तक नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 88 हजार 413, नगर पालिका कटघोरा क्षेत्र में 10 हजार 927, नगर पालिका दीपका क्षेत्र में सात हजार 234, नगर पंचायत पाली क्षेत्र में तीन हजार 733 और नगर पंचायत छुरीकला क्षेत्र में पांच हजार 238 आवेदन मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक आवेदन पाली विकासखण्ड से मिले हैं। अभी तक पाली विकासखण्ड में 56 हजार 961, कटघोरा विकासखण्ड में 27 हजार 651, कोरबा विकासखण्ड में 23 हजार 690, करतला विकासखण्ड में 37 हजार 840 और पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड में 28 हजार 336 आवेदन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के सर्वेक्षण के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस नागरिकों की गणना के लिए चिप्स द्वारा 'सीजीक्यूडीसी' नाम से मोबाईल एप्प तैयार किया गया जिसे प्ले स्टोर से इंस्टाल किया जा सकता है। मोबाइल एप्प को इंस्टाल करने के बाद एप्प में आवेदक को पंजीयन करना होगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार दो न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुमा सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अत्याय मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक साक्षरता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को प्रत्येक कार्यक्रमों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित नियमित कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल मिशन पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU